कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती,बल्कि चिंता मारती है।
– अज्ञात

कानून और न्याय तंत्र की खामियां

ऐसे में एक बदमाश को पकड़ कर फांसी चढ़ा देने से भी अपराधी, पुलिस और राजनीति के उस गठजोड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसने ऐसे दो–चार अजगर हर जिले में खड़े कर रखे हैं। कानून–व्यवस्था यूपी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती रही है।

अमर शाह।

कानपुर में एक डीएसपी समेत आठ पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या का मुख्य आरोपी विकास दूबे आखिर गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और एनकाउंटर में मारा भी गया। 3 जुलाई के हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस दिन–रात उसे ढूंढ रही थी और वह लगातार उसे चकमा दे रहा था। इस बीच विकास से जुड़े पांच लोग यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि विकास दूबे सचमुच उज्जैन पुलिस की पकड़ में आया है या यह उसकी सोची–समझी रणनीति का नतीजा है।

बहरहाल, अब जब वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो कम से कम इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए कि वह कानून और न्याय तंत्र की खामियों का इस्तेमाल करते हुए सजा से बच जाए। आखिर इन खामियों का इस्तेमाल करते हुए ही उसकी दीदादिलेरी इस सीमा तक पहुंच गई कि गिरफ्तारी के लिए आ रही पुलिस टीम को उसने पूरी तैयारी से घेरकर उस पर बर्बर हमला किया। कुल्हाड़ी से डीएसपी का पैर काट डाला, भेजा उड़ा दिया और भागते पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसा कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

इसके बाद अगर यूपी पुलिस उसके खून की प्यासी बनी घूम रही थी तो बात समझ में आती है, लेकिन अपनी हैसियत दिखाने के लिए पुलिस को टीवी कैमरों के सामने किसी गुंडे का घर और कार तोड़ने जैसे कृत्यों में उलझना पड़े, यह बात खुद में अटपटी है। 3 जुलाई की घटना के पहले और बाद पुलिस के व्यवहार में आए बदलाव पर गौर करें तो यह अटपटापन और ज्यादा उजागर होता है। जघन्यतम अपराधों के दसियों मामले दर्ज होने के बावजूद विकास दूबे का नाम पुलिस ने कानपुर के टॉप टेन मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी नहीं डाला था।

2001 में मंत्री का दर्जा प्राप्त एक नेता की थाने में घुसकर हत्या करने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उस समय थाने में एक दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन गवाही में सब मुकर गए और सबूत के अभाव में वह छूट गया। इसी मार्च महीने में डीएसपी देवेंद्र मिश्र द्वारा एसएसपी (कानपुर देहात) को विकास दूबे से स्थानीय पुलिस कर्मियों की मिलीभगत की पूरी सूचना दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले की कुल प्रगति यह रही कि एसएसपी प्रोन्नति पाकर डीआईजी हो गए जबकि शिकायत देने वाले डीएसपी 3 जुलाई की रात मार डाले गए।

ऐसे में एक बदमाश को पकड़ कर फांसी चढ़ा देने से भी अपराधी, पुलिस और राजनीति के उस गठजोड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसने ऐसे दो–चार अजगर हर जिले में खड़े कर रखे हैं। कानून–व्यवस्था यूपी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती रही है। इस साख पर लगे इतने बड़े कलंक से पीछा छुड़ाना उसके लिए आसान नहीं है। बेहतर होगा कि वह अपने प्रशासनिक तंत्र की बारीकी से पड़ताल करे ताकि आगे ऐसे संपोलियों को सांप बनने का मौका न मिले।

कठिन परिस्थितियां

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

नेत्रहीन एस के जयकुमार कहते हैं कि जीवन की कठिनाईयों से निपटने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसकी उपस्थिति को स्वीकार करें। समस्याओं के बिना जीवन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे विरोधि टीम के बिना कोई मैच! आप विरोधि टीम के बिना खेल का अभ्यास तक नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार समस्याएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मान लेते हैं कि आपको एक महान विरोधि टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है, तो क्या आप इस बात पर गर्व नहीं करेंगे कि आपका प्रतिद्वंदि मजबूत है? ऐसी परिस्थितियों में आप अपने सभी स्रोतों का इस्तेमाल का इस अवसर का सबसे अच्छा उपयोग करेंगे और अपनी सभी छिपी क्षमताओं को सामने लाकर अपनी सर्वश्रेष्ठ समर्थता के साथ इस खेल को खेलेंगे।

संपादकीय

सतर्क होने का संकेत

मध्य एशिया के पांचों राष्ट्र असीम संपदा संपन्न हैं। वे कई दशकों तक सोवियत रूस के अंग बनकर रहे लेकिन यदि चीन की पकड़ उनमें बढ़ गई तो यह मानकर चलिए कि जो चीन आज भारत से पांच गुना संपन्न है, उसे विश्व शक्ति बनते देर नहीं लगेगी। यों भी पिछले 15–20 साल में दक्षिण एशिया के साथ चीन का व्यापार 23 गुना बढ़कर 5.57 बिलियन डॉलर से 127.36 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत के पड़ोसी देशों– नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक वह सड़कें बना रहा है और श्रीलंका तथा मालदीव में भी उसने अपने कई ठिकाने बना लिए हैं। चीन चाहेगा कि ईरानी तेल तथा अन्य खदानों के उत्खनन का काम भी उसे मिले ताकि वह अपनी तेल की 70 प्रतिशत जरूरत को पूरा कर सके तथा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पांचों मुस्लिम राष्ट्रों की खदानों में दबे अकूत भंडारों का दोहन भी कर सके। इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कम्यूनिज्म में विश्वास करनेवाले चीनी नेता पाकिस्तान के 'इस्लामी तार' का फायदा उठाने से चूकने वाले नहीं हैं। हालांकि इस वक्त अफगानिस्तान में भारत के प्रति गहरी घनिष्ठता का भाव है और भारत ने वहां 3 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च भी किया है लेकिन दशकों से चीन की नजरें अफगानिस्तान की तांबे की खदानों और लोहे के पहाड़ों पर हैं। यदि पाकिस्तान के साथ–साथ ईरान में भी चीन की दुकान जम गई तो अफगानिस्तान उसकी पकड़ के बाहर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया में, जो कि वास्तव में प्राचीन भारत ही है, भारत की बजाय चीन की तूती बोलने लगेगी। भारत–चीन तनाव फिलहाल छंट रहा है लेकिन चीन–ईरान सांठ–गांठ भारत को सतर्क होने का संकेत दे रही है।

ईरान को अपना अड्डा बनाकर अमेरिका के 'पिद्दुओं' इस्राइल और सऊदी अरब को सबक सिखाने की कोशिश करेगा। जाहिर है, ऐसा होने पर फिलस्तीन, सीरिया और तुर्की के मामले भी गर्म होने लगेंगे।

नया सामरिक अड्डा

वेदप्रताप वैदिक।।

भारत के पड़ोसी देशों में चीन का दबदबा पहले से बढ़ा हुआ है लेकिन अब उसने ईरान पर भी डोरे डाल दिए हैं। एक संभावित समझौते के तहत वह ईरान में 400 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगा। अगले 25 साल के दौरान होने वाले इस विनियोग से ईरान में क्या–क्या नहीं होगा। सड़कें बनेंगी, रेलें डलेंगी, बंदरगाह खड़े होंगे। बैंकिंग और संचार को नए आयाम मिलेंगे। नए अस्पताल और स्कूल खुलेंगे। फौजी सहयोग बढ़ेगा। चीन ईरानी फौजियों को प्रशिक्षित करेगा, शस्त्रास्त्र देगा, जासूसी–सूचना का आदान–प्रदान करेगा और 'आतंकवाद' आदि से लड़ने में मदद करेगा। यह खबर निकली है उस 18 पेज के दस्तावेज से, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है।

कोई आश्चर्य नहीं कि चीन को ईरान अपना सामरिक अड्डा बनाने के लिए भी कोई जगह दे दे। ऐसा हुआ तो चीन खाड़ी और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह ईरान को अपना अड्डा बनाकर अमेरिका के 'पिद्दुओं' इस्राइल और सऊदी अरब को सबक सिखाने की कोशिश करेगा। जाहिर है, ऐसा होने पर फिलस्तीन, सीरिया और तुर्की के मामले भी गर्म होने लगेंगे। ईरान में बढ़ते चीनी प्रभाव का सीधा कुप्रभाव

भारत पर होगा। हमने अफगानिस्तान में 200 किमी की जरंज–दिलाराम सड़क इसीलिए बनाई थी कि अफगान और मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंचने के लिए हम पाकिस्तान पर निर्भर न रहें।

इस सड़क को ईरान और मध्य एशिया के राष्ट्रों से जोड़ने के लिए भारत और ईरान ने मिलकर दो समझौते किए थे। एक तो चाबहार–जाहिदान सड़क बनाने का और दूसरा चाबहार के बंदरगाह को तैयार करने का। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान–यात्रा के दौरान ये समझौते हुए थे। उसके बाद नितिन गडकरी ने तेहरान जाकर इन परियोजनाओं पर उत्साहपूर्ण घोषणाएं की थीं, लेकिन अभी तक ये अधर में ही लटकी हुई हैं। इसका मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का दुराग्रह है। ट्रंप यह मानकर चल रहे हैं, रिचर्ड निक्सन की तरह कि ईरान 'दुष्टता का अवतार' है। वह परमाणु बम जरूर बना रहा है। इसीलिए ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के उस परमाणु समझौते से अलग कर लिया है, जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और छह राष्ट्रों ने मिलकर ईरान के साथ किया था। दो वर्ष की कड़ी जद्दोजहद के बाद इस समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंध उठा लिए गए थे और ईरान ने अपने परमाणु–संयंत्रों पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी स्वीकार कर ली थी।

ट्रंप ने न सिर्फ ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए, बल्कि उन्होंने ईरानी सरकार के साथ सहयोग करनेवाले देशों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। इसके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। उसके तेल की बिक्री काफी घट गई। अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने ईरान से लेन–देन के व्यवहार पर रोक लगा दी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा चलाई जा रही चाबहार और जाहिदान के बीच की सड़क परियोजनाओं पर प्रतिबंधों में छूट दे दी थी लेकिन वे चलाई नहीं जा सकीं क्योंकि उनके लिए उपकरणों, यंत्रों और भागीदारों को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोपीय देशों के सहयोग से चलनेवाली कई अन्य परियोजनाएं भी ठप होने लगी थीं।

सूडोकु नवताल-5309

मध्यम

4	6		3		8	9		7
	1		9		6		5	4
						8		
	4		5				8	
2		5		4		6		1
	3				1		7	
		3						
5	9		7		2		6	
7		6	4		3		9	2

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5308 का हल

5	7	2	3	8	4	1	9	6
8	6	1	9	2	5	7	3	4
3	9	4	1	6	7	5	8	2
2	5	7	4	1	3	8	6	9
4	8	6	5	9	2	3	7	1
1	3	9	6	7	8	4	2	5
6	2	3	7	4	1	9	5	8
9	4	5	8	3	6	2	1	7
7	1	8	2	5	9	6	4	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव

मोहन। 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी चिन फिंग ने अपनी तेहरान–यात्रा के दौरान ईरान के साथ व्यापक सामरिक और आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव रखा था लेकिन ईरान ने पिछले चार साल से उसे हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन अभी तो मरता, क्या नहीं करता। शीघ्र ही ईरानी संसद इस समझौते पर मुहर लगानेवाली है। यदि चीन और ईरान का यह समझौता लागू हो गया तो पाकिस्तान और ईरान की घनिष्ठता बढ़ेगी। इन दोनों सुन्नी और शिया देशों में कई तरह के तनाव, खिंचाव हैं। चीन धीरे–धीरे उन्हें दूर करेगा और अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाएगा। उसकी 'रेशम महापथ' (सिल्क रूट) की विशाल योजना को जबर्दस्त उठान मिलेगा। इस समय ईरान यह कोशिश भी करेगा कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चाबहार के बीच सीधा संबंध बन जाए। ग्वादर बंदरगाह पर चीन पूरी तरह से हावी है। चीन को ईरान 'बदरे–जस्क' बंदरगाह भी दे सकता है, जो चाबहार से 350 किमी दूर है।